

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्रमांक/एफ-5/921/2019/10-11/789 भोपाल, दिनांक 27-2-20
प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल,
राजगढ़, मध्यप्रदेश।

विषय:- राजगढ़ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु कुण्डालिया बहु ग्रामीण
जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.540 हेक्टेयर
वन भूमि मध्य जल निगम मार्यादित, PIU राजगढ़ को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, भोपाल का पत्र क्रमांक/मा0चि0/4769 दिनांक 18.12.2019

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य
वन संरक्षक, भोपाल एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन
गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन
को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित
शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 3,38,040/- is to be paid for the 0.540 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- No felling of trees shall be done.
- 5- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- 6- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.

- 7- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 9- No labour camp shall be established on the forest land.
- 10- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 13- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 14- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 15- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 16- No work shall be done during night.
- 17- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

(सुनील अग्रवाल)
22/4/20

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/883/2019/10-11/790
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-2-20

- 1- मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 - 2- महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मार्यादित, PIU राजगढ़, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।</p>	<p>राजगढ़ जिले में जमीनों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु कुण्डालिया बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.540 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 जल निगम मार्यादित, 111। राजगढ़ को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।</p>
----	---	--

तिथि:-28.12.2019

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal